शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 42 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 13 – 20 अक्तूबर 2025 मूल्य पांच रूपये

अभी लटक सकता है प्रदेश अध्यक्ष का फैसला

शिमला/शैल। हिमाचल कांग्रेस में एक लम्बे समय से यह तय नहीं हो पा रहा है कि पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाये। अब तक करीब एक दर्जन नेताओं के नाम अध्यक्ष की चर्चा में आ चुके हैं। कई मंत्रियों के नाम चर्चा में उछले और यह आया कि मंत्री लोग अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ मंत्री पद भी साथ रखना चाहते हैं। फिर यह आया कि रोहित ठाकुर मंत्री पद अध्यक्ष बनने के लिये छोड़ने को तैयार हैं। रोहित के साथ ही पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर का नाम चर्चा में जुड़ गया। लेकिन इनमें से किसी का नाम फाइनल होने से पूर्व ही इस चर्चा में विधायक आर.एस.बाली का नाम जुड़ गया। पिछले दिनों जब प्रदेश के छः बार मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर जिस तरह की भीड़ इस अनावरण पर इकट्ठी हो गयी थी उससे यह चल पड़ा है की हॉलीलॉज को नजर अन्दाज करना संभव नहीं होगा। कुल मिलाकर जिस तरह की परिस्थितियां अब तक निर्मित हो चुकी हैं उनसे यही लगता है कि अध्यक्ष का फैसला अभी और लटक सकता है। नया अध्यक्ष और नये पदाधिकारी बनाये जाने में हो रही देरी के लिये प्रदेश के सारे धड़ों के नेता हाईकमान को दोषी ठहरा चुके हैं। यह दोषी ठहराने में ही सारा खेल अटका हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हाईकमान प्रदेश पर पूरी नजरें लगाये हुये बैठा है। हाईकमान जिस तराजू पर तोलकर प्रदेश नेतृत्व का आकलन कर रहा है यह समझना आवश्यक है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद देश में लोकसभा और हरियाणा तथा महाराष्ट्र विधानसभाओं के चुनाव हुये हैं। हिमाचल में कांग्रेस का सहप्रभारी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होकर आज केन्द्र में मंत्री बना हुआ है। लेकिन हिमाचल के किसी नेता को इसकी भनक तक नहीं लगी। लोकसभा में पार्टी चारों सीटें हार गयी। राज्य सभा की सीट पर भी हार गयी। आज प्रदेश में ई.डी., सी.बी.आई. और आयकर विभाग जैसी सारी केंद्रीय एजैन्सियां दखल दे चुकी हैं। इस दखल में हिमाचल के सहप्रभारी रहे और फिर भाजपाई बने नेता की भी भूमिका कही जा रही है। लेकिन हिमाचल का कोई भी नेता इस सब का पूर्व आकलन करके हाईकमान को अलर्ट नहीं कर पाया। बल्कि हिमाचल सरकार अपने कुछ विवादित फैसलों के लिये हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चर्चा में रह चुकी है। व्यवहारिक तौर पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार केन्द्र सरकार के आर्थिक एजैन्डे के बहुत निकट चल रही है। ऐसे में जो सरकार हाईकमान को न तो कोई लोकसभा की सीट दे पायी और न ही राज्यसभा की उसके राजनीतिक आकलन पर कोई भी हाईकमान कितनी निर्भरता बना सकती है। इसी सरकार की कार्यशैली के कारण प्रियंका गांधी का नाम बैंस प्रकरण में चर्चा का विषय बन गया है। इस समय सी.बी.आई. और ई.डी. जिन मामलों में प्रदेश में दखल दे चुकी है उनमें अगले कुछ माह में बड़ा कुछ घटने की संभावनाएं बनती जा रही हैं। कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक और स्व. विमल नेगी की मौत के प्रकरणों में चल रही जांच के छींटे बहुत दूर तक जायेंगे यह तय है। इन जांचों का प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर भी गहरा असर पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक राहुल गांधी प्रदेश के इन हालातों की पूरी जानकारी रख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस हाईकमान प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लेगी। क्योंकि जब प्रदेश में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव अभी होने ही नहीं जा रहे हैं जहां कार्यकर्ताओं की सीधी आवश्यकता होती है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी का फैसला कुछ दिन और लटक जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुये तीन वर्ष होने जा रहे हैं। इन तीन वर्षो में कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार के किसी फैसले पर जनता में सरकार की वकालत कर पायेगा क्योंकि पार्टी दस गारंटीयां देकर सत्ता में आयी थी आज इन गारंटीयों के आईने में कार्यकर्ता के पास क्या पॉजिटिव है जिसको लेकर जनता में जाया जायेगा। क्या कोई विधायक अपने ही गांव से दस आदमी ऐसे दिखा पायेगा जो कहे कि उन्हें गारंटीयों का लाभ मिल रहा है। जब सरकार हर समय वित्तीय संकट का ही राग अलापति रही है तो उसके पास कुछ भी करने के लिये पैसा ही कहां था। इस तरह जो व्यवहारिक स्थितियां बनी हुई है उनके परिदृश्य में प्रदेश अध्यक्ष का फैसला अभी और लटकने की संभावना है।

बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों को मुआवजा देने पर आएगी नई नीति

शिमला/शैल। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश

के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए तीन प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किश्त अक्तूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ नवम्बर माह में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2025 तक का बकाया कर्मचारियों के खातों में अक्तूबर माह में जमा कर दिया जाएगा। वहीं जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक की बकाया राशि के बारे में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

शिमला में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के आम अधिवेशन के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड के कर्मचारियों की यूनियन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद पुरानी पेंशन योजना देने पर आने वाले समय में विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में सुधार करने की आवश्यकता है और कर्मचारियों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। आज ऊहल प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन का खर्च 27 रुपये प्रति यूनिट आ रहा है, जिसके लिये बोर्ड के बड़े अधिकारी जिम्मेदार है। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों का खर्च प्रति यूनिट 2.50 रुपये है, क्योंकि बोर्ड में अधिकारियों की बहुत अधिक संख्या है और छोटे कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड में कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने के लिए 2200 करोड़ रुपये जारी किये है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 2023 से सितंबर 2025 तक कंपनी ने पेंशनधारकों को ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण और पेंशन बकाया के रूप में कुल 662.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और इसी वर्ष के अंत तक 70 करोड़ का भुगतान और किया जाएगा। सभी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान को केन्द्रित कर दिया गया है और इसे साप्ताहिक आधार पर किया जा रहा है, जिसमें कोई लंबित राशि नहीं है। उन्होंने बोर्ड को अपने आउटसोर्स कर्मचारियों की किसी हादसे में घायल होने पर मुआवजा नीति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड की रुकी हुई पदोन्नतियां भी तुरंत प्रभाव से की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दी तो हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेताओं के दबाव में केंद्र सरकार ने राज्य की एडिशनल बॉरोइंग बंद कर दी। ओपीएस को वापिस लेने के लिए बार-बार केंद्र से पत्र भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए आने वाले तीन-चार महीने आर्थिक तंगी के है, लेकिन जल्द ही आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी।

राज्यपाल ने नारी सेवा सदन और बालिका आश्रम का दौरा किया

शिमला/शैल। दिवाली उत्सव से पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और उनकी धर्मपत्नी एवं राज्य रेड

क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष जानकी शुक्ला ने आज जिला शिमला के मशोबरा स्थित नारी सेवा सदन और बालिका आश्रम का दौरा किया। उन्होंने आश्रम में रह रही महिलाओं और बालिकाओं को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और मिठाइयां वितरित कीं।

इस अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा जीवन को आकार देने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बालिकाओं से आग्रह किया कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने कहा कि अपना उत्साह कभी कम न होने दें और सदैव राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का प्रयास करें।

शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहां के त्यौहार राज्य की समृद्ध देव संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हमारी भावनाएं और मूल्य सदैव इन दिव्य परंपराओं से जुड़े रहने चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि ऐसे संस्थानों में रह रहे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के समान अवसर दिए जाने चाहिए। उन्हें सह-पाठयक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपना कौशल और आत्मविश्वास प्रदर्शित करने का उपयुक्त मंच मिल सके।

राज्यपाल के सचिव सी. पी. वर्मा, जिला प्रशासन के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने युवाओं से अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाने का आहवान किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश

विश्वविद्यालय, शिमला में मॉडल संयुक्त राष्ट्र एवं युवा संसद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है तथा इन युवाओं की रचनात्मकता और ऊर्जा इसे निकट भविष्य में एक विकसित देश का रूप प्रदान करेगी।

इस संगोष्ठी का आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा विकसित भारत @ 2047 पहल के अंतर्गत किया गया।

राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करते हैं। इससे उन्हें वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की दिशा में सार्थक योगदान करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने इस बात की सराहना की कि विद्यार्थी अपनी संस्कृति को जीवंत रखते हुए राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। यह सांस्कृतिक जागरूकता हमारे लोकतंत्र की आत्मा और भारत की वास्तविक पहचान है।

राज्यपाल ने जेन-जेड के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं का अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ गहरा जुड़ाव है। उन्होंने कुल्लू दशहरा और अन्य धार्मिक उत्सवों जैसे आयोजनों के दौरान इन मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को स्वयं देखा है। कुल्लू दशहरा में युवा श्रद्धालु भगवान रघुनाथ के रथ को अपार श्रद्धा के साथ खींचते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनके अटूट सम्मान को दर्शाता है। युवाओं में ऐसी भावना और समर्पण भारत को एक बार फिर विश्व गुरु के रूप में उभरने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। हिमाचल के युवाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की सादगी, ईमानदारी और मानवता को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह अपनी ऊर्जा संघर्ष में न लगाकर राष्ट्र निर्माण में लगाएं।

विश्वविद्यालयों में हिंसात्मक गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने छात्र संगठनों का आहवान किया कि शारीरिक संघर्षों के बजाय वे वैचारिक संघर्ष में शामिल हों। शैक्षणिक वातावरण को बाधित करने से किसी को कोई लाभ नहीं होता, इसलिए युवाओं को अपनी ऊर्जा राष्ट्र विकास में लगानी चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत के ऊर्जावान युवा इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार-विमर्श करेंगे और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देंगे।

विचारों की विविधता को अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए, शुक्ला ने कहा कि यही लोकतंत्र की असली ताकत है। उन्होंने युवाओं को यह भी याद दिलाया कि अधिकार जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने समकालीन मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया।

राज्यपाल ने युवाओं से अपने विचारों, आदर्शों और कार्यों के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया।

कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला की कुलपति प्रो. प्रीति सक्सेना ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन पर बल देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे सुंदर पहाड़ी राज्य में विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस अवसर पर डीन, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, छात्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कोटला-बड़ोग नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र में उपलब्ध करवाई जाएंगी अत्याधुनिक सुविधाएं: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिला के कोटला-बड़ोग में आधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के निर्माण को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केन्द्र में कुल 100 बिस्तरों की क्षमता होगी तथा पुस्तकालय, व्यायामशाला, खेल गतिविधियों, योग साधना और कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा भी होगी। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिकित्सकों और नर्सों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती भी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 534.36 लाख रूपये स्वीकृत किए हैं और अगर आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

बैठक में उपायुक्त सोलन और सिरमौर वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिए कि इस केन्द्र की स्थापना के लिए पशु पालन विभाग की भूमि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को स्थानान्तरित की जाए।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, प्रधान सचिव विधि राजीव बाली, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सुमित किमटा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने दीपावली पर्व पर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि यह रोशनी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। इस दिन दीपक न केवल घरों को सजाने के लिए, बल्कि जीवन के एक गहन सत्य को संप्रेषित करने के लिए भी जलाए जाते हैं।

जयराम ठाकुर ने दीपावली पर दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दीपों के पावन पर्व दीपावली के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने कहा कि यह पर्व अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। जिस प्रकार भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने पर सम्पूर्ण नगर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा था, उसी भावना के साथ आज भी हर घर में यह त्यौहार मनाया जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि दीपावली का यह शुभ पर्व सभी के जीवन में खुशियों, नई उमंग और समृद्धि का संदेश लेकर आये। उन्होंने कामना की कि माता लक्ष्मी और भगवान श्रीराम की कृपा से प्रत्येक परिवार का जीवन सुख, शांति और सौभाग्य से परिपूर्ण हो। हर व्यक्ति स्वस्थ्य और समृद्ध हो।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह पर्व हमें अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर सद्भाव, सेवा और सकारात्मकता के दीप जलाने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री ने आरजीएसएसवाई के अंतर्गत ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी

आवास ओक ओवर से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के अंतर्गत 18 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया।

शिमला जिले के चार, कांगड़ा और किन्नौर जिलों के तीन-तीन, चंबा, कुल्लू और सोलन जिलों के दो-दो तथा हमीरपुर और सिरमौर जिलों के एक-एक युवा को ई-टैक्सियां प्रदान की गई। राज्य सरकार ने इन टैक्सियों की खरीद के लिए 1.28 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है और अब तक राज्य के 79 पात्र युवाओं को 5.64 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि इन ई-टैक्सियों को सरकारी विभागों और निगमों के साथ जोड़कर पांच वर्षों की अवधि के लिए आय भी सुनिश्चित होगी, जिसमें दो वर्ष के विस्तार का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 40 पात्र युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 2.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 66.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य सरकार प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और ई-वाहनों को बढ़ावा देना हिमाचल प्रदेश को देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने मेडिकल टेस्टों की ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐप विकसित करने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के अस्पतालों में होने वाले मेडिकल टेस्टों की ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐप विकसित करने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग से समन्वय स्थापित कर एक महीने के भीतर ऐप विकसित करेगा ताकि लोगों को सुलभ एवं कौशलैस सेवाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अस्पतालों में टेस्टों की फीस जमा करवाने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा तथा उन्हें गुणात्मक एवं निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त चिकित्सकों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी निर्धारित कर सकेंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग में अनेक सुधार कर रही है तथा प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि लोगों को स्वास्थ्य जांच एवं इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी वर्षों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास और विस्तार पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि व्यय करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र वर्तमान प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है तथा लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं।

नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इसी वर्ष शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी:मुख्यमंत्री

एमआरआई के लिए 28 करोड़ रुपये, कैथ लैब के लिए 12 करोड़ जारी किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक, जिला मण्डी के कार्यक्रम आईआरआईएस.2025 की

अध्यक्षता की। उन्होंने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इसी वर्ष रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि यहां एमआरआई मशीन लगाने के लिए 28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसे दो माह में स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेरचौक में कैथ लैब के लिए राज्य सरकार ने 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 9 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं। जल्द ही सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स, दिल्ली की तर्ज पर एक ही ब्लड सैंपल से 100 टेस्ट किए जाएंगे। स्मार्ट डायग्नोस्टिक लैब के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने प्रदेश का खजाना लुटाया। अगर यह पैसा पिछली सरकार सही इस्तेमाल करती, तो आज स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होतीं। उन्होंने कहा कि जब देश विदेश में हिमाचल के डॉक्टर मिलते हैं तो सुखद एहसास होता है। हमारे डॉक्टर प्रतिभाशाली हैं लेकिन पुरानी तकनीक के कारण उन्हें मरीजों के इलाज में परेशानी आती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नीशियन की कमी दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके अतिरिक्त डिपार्टमेंट ऑफ एमरजैंसी मेडिसिन में 38 पद स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान सरकार को प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों की खराब हालत विरासत में मिली लेकिन आज एम्स स्तर की तकनीक मेडिकल कॉलेजों में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शिमला चमियाणा अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी गई है जहां 45 ऑपरेशन रोबोट के माध्यम से हुए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से ही नीतिगत बदलाव किया ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं, जिससे आज शिक्षा के क्षेत्र में 60 प्रतिशत तक सुधार आया है। हम 21वें स्थान से बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए स्कूल तो खोल दिए लेकिन सुविधाएं नहीं थी, इसलिए हमें उन्हें बंद करने का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं लेकिन बच्चों से बातचीत के दौरान उनमें आत्मविश्वास की कमी पाई। लेकिन सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसके लिए सभी अध्यापक बधाई के पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोल जा रहे हैं। पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की गई है और 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई आधारित बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति छात्र जीवन से शुरू की और 26 वर्ष की आयु में शिमला नगर निगम का पार्षद बने। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सफलता हर बार नहीं मिलती है, लेकिन हमें असफलता से कभी निराशा नहीं होना चाहिए तथा सफलता पाने के लिए सभी को मेहनत से कार्य करना चाहिए।

सुक्खू ने छात्रों को 5 लाख रुपये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए देने की घोषणा की।

शिमला में रोपवे परियोजना को मिली केंद्र की मंजूरी: उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य की बहुप्रतीक्षित रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डवेल्पमेंट प्रोजेक्ट को केंद्र

सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत चरण-1 की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यह परियोजना शिमला शहर में शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह परियोजना लगभग 13.79 किलोमीटर लंबी रोपवे लाइन को विकसित करने का लक्ष्य रखती है जो शिमला के प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ेगी। लगभग 1734.70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की जा रही है, इससे न केवल शहर में यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह एक टिकाऊ और हरित समाधान होगा।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के लिए 6.1909 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की सैद्धांतिक मंजूरी आधार पर दी गई है, जिसमें सभी पर्यावरणीय और संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इस रोपवे परियोजना के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पर्यटकों को एक नया अनुभव प्राप्त होगा।

अग्निहोत्री ने कहा कि शिमला के नागरिकों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है। यह परियोजना राज्य सरकार के संकल्प 'हरित और आधुनिक हिमाचल' की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने केंद्र सरकार और विशेष रूप से पर्यावरण मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इस महत्त्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की।

उन्होंने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी निर्माण गतिविधियां वन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगी।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोपवे शिमला के परिवहन तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इससे यातायात का दबाव कम होगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दीपावली का त्यौहार न केवल घरों को ही बल्कि हमारे मन और समाज को भी रोशनी से आलोकित करता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आहवान किया कि इस अवसर पर सब मिलकर शांति, सौहार्द और एकता का संदेश फैलाएं तथा एक समृद्ध और उज्ज्वल प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें। उन्होंने दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों के सुखी जीवन एवं समृद्धि की मंगल कामना की।

उप-मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली पर्व हमें प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि इस पर्व को आपसी मेल-जोल की भावना के साथ मनाएं ताकि सबके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैले।

स्टार्ट-अप एंड स्टूडेंट इनोवेशन पॉलिसी से युवाओं के स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा:राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमुडा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि युवाओं के स्टार्ट-अप को हिमुडा स्टार्ट-अप एंड स्टूडेंट इनोवेशन पॉलिसी के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति के तहत हिमुडा द्वारा एक वर्ष के लिए 25 लाख रुपये के स्टार्ट-अप फंड का प्रावधान किया

गया है और युवाओं के स्टार्ट-अप को प्रति प्रस्ताव 5 लाख रुपये की फंडिंग दी जाएगी। नीति का उद्देश्य प्रदेश में नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करना है। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह नीति प्रदेश में जीवन्त स्टार्ट-अप इको सिस्टम को आकार देने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने हिमुडा को क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत जिला कांगड़ा के नरघोटा में पर्यटन गांव का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को विस्तार प्रदान करने के दृष्टिगत हिमुडा को आध्यात्मिक नगर क्षेत्र परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल को सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत आइटी टाउनशिप परियोजनाओं पर भी कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने शिमला शहर में भीड़-भाड़ कम करने के लिए जाठिया देवी में निर्मित की जा रही माउंटेन सिटी परियोजना की भी समीक्षा की।

बैठक में निजी भागीदारों के साथ रियल इस्टेट परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। हिमुडा द्वारा लम्बे समय से गैर-क्रियाशील पदों का युक्तिकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त हिमुडा की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 46 पदों को भी सृजित किया गया है।

हिमाचल ने जीती महत्त्वपूर्ण कानूनी लड़ाई, वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति से मिलेंगे 401 करोड़ रुपये

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और महत्त्वपूर्ण कानूनी सफलता प्राप्त की है जिसके अंतर्गत मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड एमआरएल कंपनी को वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति से 401 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। अब राज्य इस कंपनी का एकमात्र स्वामी बन जाएगा।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि राज्य संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी के बैंक में जमा राशि, शेयर होल्डिंग्स और पूंजी के विरुद्ध अग्रिम राशि के 50 प्रतिशत का एकमात्र स्वामी बन गया है। उच्च न्यायालय के 14 अक्तूबर, 2025 के निर्णय के अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनी के लगभग 320 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस राज्य को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने मध्यस्थ निर्णय के अनुसार राज्य को 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। संयुक्त उद्यम कंपनी में ईस्ट इंडिया होटल्स ईआईएच की संपूर्ण शेयर होल्डिंग 13 करोड़ रुपये की राशि राज्य को हस्तांतरित की जाएगी।

इसके अलावा, राशि का केवल 50 प्रतिशत यानी 68 करोड़ रुपये ईआईएच को हस्तांतरित किए जाएंगे। यह धनराशि ईआईएच द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी में जमा की गई 136 करोड़ रुपये की पूंजी के बदले में वापस किए जाएंगे। इससे राज्य को 68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि एमआरएल पहले वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति का संचालन करने वाली ईस्ट इंडिया होटल और राज्य की संयुक्त उद्यम कंपनी थी।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह कानूनी लड़ाई लगभग 30 वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के विशेष हस्तक्षेप और प्रयासों के कारण, सर्वोच्च न्यायालय ने 20 फरवरी, 2024 के अपने आदेश में वाइल्ड फ्लावर हॉल की संपूर्ण संपत्ति का कब्जा और स्वामित्व राज्य के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद, राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2025 को संपत्ति का भौतिक कब्जा और स्वामित्व प्राप्त कर लिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देश के प्रमुख वकीलों की मदद से न्यायालय में इस मामले को मजबूती से लड़ा और राज्य के लोगों के हित में जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की। पहले राज्य को इस संपत्ति से कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वर्तमान राज्य सरकार के सक्रिय प्रयासों के कारण राज्य को सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

इससे पहलेएक अन्य मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी के संबंध में राज्य के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिया था। न्यायालय ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी को निर्देश दिया था कि वह राज्य को 12 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान करे। इस निर्णय के आने से राज्य को प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये से अधिक की आय हो रही है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने दोहराया कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी और किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं करेगी।

आपको मानवता पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। मानवता एक महासागर है, अगर महासागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो महासागर गंदा नहीं हो जाता।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या बिहार चुनाव देश के भविष्य की दशा तय करेंगे?

बिहार विधानसभा चुनावों का देश की राजनीति पर दुरगामी प्रभाव पड़ेगा यह निश्चित है। बल्कि इन चुनावों से देश का राजनीतिक चरित्र ही बदल जायेगा यह कहना ज्यादा सही होगा। क्योंकि इन चुनावों से पूर्व देश के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बहुत ही गंभीर आरोप लग चुके हैं। इन आरोपों का व्यवहारिक प्रभाव केंद्र सरकार और शीर्ष न्यायपालिका पर भी देखने को मिल गया है। केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ खड़ी हो गयी है और शीर्ष अदालत ने उस याचिका को अस्वीकार कर दिया है जिसमें इन आरोपों की जांच के लिये एक एसआईटी गठित करने की मांग की गयी थी। जब चुनाव आयोग शीर्ष अदालत और केंद्र सरकार सब एक साथ विश्वसनीयता के संकट में आ जाये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सब का अंतिम परिणाम क्या होगा। बिहार में हुये एस आई आर पर ही इन चुनावों से पूर्व शीर्ष अदालत कोई अंतिम फैसला नहीं दे पायी है इसको आम आदमी कैसे देखेगा यहां अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार चुनावों की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में दस-दस हजार ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। इससे प्रधानमंत्री का 'चुनावी रेवड़ी' संस्कृति पर भी व्यवहारिक पक्ष सामने आ जाता है। पिछले लोकसभा चुनावों से पूर्व राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' का परिणाम था कि भाजपा अपने दम पर केंद्र में सरकार नहीं बना पायी उसे नीतीश और नायडू का सहयोग लेना पड़ा है। लोकसभा चुनावों के बाद हुये हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर इतना कुछ देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि इसके कारण राहुल गांधी को चुनाव आयोग पर हमला बोलने के लिये पर्याप्त सामग्री मिल गयी। राहुल गांधी के चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह के प्रमाणिक साक्ष्य जुटाकर पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से हमला बोला है उससे पूरे प्रदेश में 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान चल निकला है। पिछले ग्यारह वर्षो में केंद्र सरकार ने जो कुछ किया है उस पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। सारे चुनावी वायदे आज सवालों के घेरे में आ खड़े हुये हैं। बेरोजगारी और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अभी सरकार ने जीएसटी संशोधन से जो राहत आम आदमी को पहुंचाने का फैसला लिया है उसका आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिला। क्योंकि बाजार में वस्तुओं के दाम व्यवहारिक रूप से कम नहीं हो पाये हैं। इस पृष्ठभूमि में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव हर राजनीतिक दल, नेता और आम आदमी सबकी व्यक्तिगत परीक्षा होगी यह तय है। बिहार में कुल 7.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 1.63 करोड़ मतदाता वह हैं जो बीस से अठाईस वर्ष के हैं और 14 लाख वह हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। यह वह लोग हैं जो बेरोजगारी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। जिनके लिये अब तक चुनावी वायदे आज सत्ता से सवाल बन गये हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में यह लोग ही सबसे बड़े भागीदार थे। इनका भविष्य ही सबसे ज्यादा दाव पर लगा है। इसी युवा ने नेपाल और बांग्लादेश में सत्ता के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है। इसलिये आज बिहार चुनाव में आम आदमी के सामने सारे राष्ट्रीय प्रश्न खुलकर खड़े हैं। इन चुनावों के परिणाम देश की राजनीतिक स्थिति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाले हैं जिसका परिणाम दूरगामी होगा।

आधुनिक भारतीय मुस्लिम समाज में दहेज का प्रचलन और लड़कियों की बढ़ती मौतें

गौतम चौधरी

इन दिनों आधुनिक भारतीय मुस्लिम समाज में, हिन्दू समाज की कुछ पारंपरिक बुराइयां प्रवेश कर गयी है। इसके कारण मुस्लिम समाज का पारिवारिक ताना-बाना प्रभावित होने लगा है। उन्हीं बुराइयों में से एक दहेज है। वैसे तो दहेज एक सामाजिक बुराई जिसने लंबे समय से दक्षिण एशियाई समाज को जकड़ रखा है। इस बुराई के कारण न जाने कितने मासूम बच्चियों को जान गवाना पड़ रहा है। परिवार के आपसी रिश्ते टूट रहे हैं और महिलाओं की गरिमा कलंकित हो रही है। बड़े लंबे समय तक भारतीय प्रायद्वीप का मुस्लिम समाज इस कुप्रथा से बंचित रहा लेकिन आधुनिक काल में इस समाज को भी इसने बुरी तरह जकड़ लिया है। भारतीय प्रायद्वीप के अमूमन सभी धर्म-पंथों में इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि यह गैरकानूनी है लेकिन इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन नहीं हो पा रहा है। यहां एक बात बता दें कि मुसलमानों में इसका मौजूद होना चौंकाने वाला है, क्योंकि इस्लाम इसे स्पष्ट रूप से निषिद्ध करता है। दहेज को इस्लामिक कानून के अनुसार नाजायज माना गया है। हाल के वर्षो में दहेज की मांग से जुड़ी उत्पीड़न, यातना और यहाँ तक कि मौत की घटनाओं ने मुस्लिम समुदाय को झकझोर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 22 वर्षीय मुस्लिम युवती गुलफिज़ा इसका ताज़ा शिकार बनी, जिसे उसके पति ने 10 लाख रुपये की मांग पूरी न करने पर तेज़ाब पीने के लिए मजबूर किया और वह खून उलटी करते हुए मर गयी।

इस्लाम का दहेज पर रुख़ और भारतीय मुस्लिम लड़कियों के सामने खड़ी इस त्रासदी को समझना बेहद ज़रूरी है। इस्लाम में दहेज जहेज़ या दहेज का कोई सिद्धांत नहीं है। इसके बजाये धर्म, मेहर का आदेश देता है। मेहर एक अनिवार्य तोहफ़ा जो दूल्हा, दुल्हन को देता है। यह सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और उसके अधिकारों की मान्यता का प्रतीक है। मेहर केवल पत्नी की संपत्ति है, जिस पर न पति का और न ही ससुराल का कोई अधिकार है। मेहर एक प्रकार की रकम होती है, निकाह से पहले तय कर दिया जाता है। यह रकम ससुराल पक्ष की ओर से तय किया जाता है। यह वह रकम है, जो विपरीत परिस्थिति में दुल्हन को ससुराल पक्ष की ओर से देय होता है। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में भी हक होता है। इसको इस्लामिक कानून में जायज ठहराया गया है। इसलिये मुस्लिम समाज में दजेज का कोई स्थान ही नहीं है। बरेलवी फिरके के इस्लामिक विद्वान तुफैल खान कादीरी साहब का कहना है कि विवाह समारोह में जो फालतू के खर्च किए जाते हैं, उसे भी इस्लाम में हराम माना गया है।

पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर देकर कहा कि सबसे अच्छी शादी वह है जिसमें आर्थिक और सामाजिक बोझ सबसे कम हो। रिवायतों में आता है कि उनकी बेटियों की शादियां सादगी से हुई, बिना किसी दिखावे या भौतिक अपेक्षा के। इसलिए आज जो दहेज प्रथा देखी जाती है, वह इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ़ एक बिदअत है।

फिर भी, दक्षिण एशियाई मुस्लिम समाज में दहेज ने जगह बना ली है। ऐसा सांस्कृतिक कुप्रभाव, औपनिवेशिक दौर के व्यक्तिगत क़ानूनों और गैर-इस्लामी परंपराओं की नकल के कारण हुआ है। इस्लाम जिस प्रथा को अत्याचार कहकर नकारता है, वही कई परिवारों में सामान्य व्यवस्था बन गई है। भारत में हर साल हज़ारों दहेज हत्या के मामले दर्ज होते हैं और इसमें मुस्लिम महिलाओं की भी संख्या अच्छी खासी होती है। आंकड़ों में हिंदू समुदाय के मामले अधिक दिखते हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं भी दहेज की क्रूरता से अछूती नहीं हैं।

भारतीय मुसलमानों में दहेज की मौजूदगी आस्था और अमल के बीच गहरी खाई को उजागर करती है। एक ओर मुसलमान कुरान और सुन्नत के पालन पर गर्व करते हैं, जहां महिलाओं के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। दूसरी ओर व्यवहार में कई परिवार बेटियों को बोझ मानते हैं और उन्हें ऐसी प्रथा के हवाले कर देते हैं जिसे इस्लाम साफ़-साफ़ नकारता है। यह इस्लामी सिद्धांतों से गद्दारी है, जो न केवल महिलाओं को चोट पहुंचाती है बल्कि समाज के नैतिक ढांचे को भी खोखला करती है। इस्लामिक पवित्र ग्रंथ कुरन दूसरों का धन अन्यायपूर्वक खाने से मना करता है, जबकि दहेज मांगना एक प्रकार का ज़बरन वसूली है जिसे रिवाज का नाम दिया गया है। वैसे भी यह एक प्रकार का अन्याय है।

इन चौंकाने वाली मौतों से आगे भी, अनगिनत मुस्लिम महिलाएं दहेज की वजह से निरंतर मानसिक दबाव में जीती हैं। नई-नई दुल्हनों को बार-बार याद दिलाया जाता है कि उनके मायके ने क्या दिया या नहीं दिया। यह अपमान उनकी गरिमा छीन लेता है और वैवाहिक जीवन को विषाक्त बना देता है। माता-पिता भी बेटियों के जन्म पर निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि बेटी केवल संसाधनों का बोझ बनेगी। इससे बेटियों की शिक्षा, करियर और देखभाल की उपेक्षा होती है, जो अशिक्षा, कम उम्र की शादियों और भेदभाव को और बढ़ावा देता है।

भारत का दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज मांग को अपराध घोषित करता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और 80 दहेज मृत्यु से संबंधित है। लेकिन इन क़ानूनों का पालन की प्रक्रिया बेहद कमज़ोर है। पीड़िताएं अक्सर धमकियों, परिवार के असमर्थन या सामाजिक बदनामी के डर से चुप रहती हैं। पुलिस जांच ढीली होती है और मुक़दमे वर्षो तक चलते हैं, जिससे परिवारों को न्याय नहीं मिल पाता।

चूंकि मुस्लिम समाज धार्मिक रूप से सशक्त है, इसलिए मुस्लिम नेताओं और संगठनों को सिर्फ़ क़ानूनी उपायों पर निर्भर रहने के बजाये धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का सीधा सामना करना चाहिए। मस्जिदों में खुत्बे प्रवचन, शैक्षिक अभियानों और सामुदायिक प्रयासों के ज़रिए दहेज की सामान्यीकरण को तोड़ना ज़रूरी है। भारतीय मुस्लिम लड़कियों की दहेज से जुड़ी बढ़ती मौतें इस्लामी आदर्शो और ज़मीनी हक़ीक़तों के बीच खतरनाक अंतर को दिखाती हैं। इस सामाजिक बुराई से खोई हर ज़िंदगी पूरे समुदाय की अंतरात्मा पर कलंक है। अगर भारतीय मुसलमान न्याय, करुणा और महिलाओं की गरिमा पर आधारित अपनी पहचान फिर से पाना चाहते हैं, तो उन्हें दहेज के खलिाफ़ एक अडिग लड़ाई लड़नी होगी।

राज्य सरकार ने जनजातीय विकास को गति दी

35,000 से अधिक जनजातीय परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का निवेश

समावेशी और संतुलित विकास को प्राथमिकता देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यो पर पिछले अढाई वर्षो में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ जनजातीय विकास को गति प्रदान की है। इस पहल से बेहतर बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच, आजीविका सृजन कार्यक्रमों और बेहतर सामाजिक सेवाओं के माध्यम से 35,000 से अधिक जनजातीय परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हुआ है। नई सड़कें, पुल, आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं और समुदाय परिसंपत्तियों तथा हस्तक्षेप सामाजिक – आर्थिक परिदृष्य में लगातार बदलाव ला रहे हैं।

जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 2022 – 23 के लिए 855 करोड़ रुपये, 2023 – 24 में 857.14 करोड़ रुपये, 2024 – 25 में 890.28 करोड़ रुपये और 2025 – 26 के लिए 638. 73 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजटीय प्रावधानों के साथ एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार किया है। सड़क, पुल, परिवहन अवसंरचना और सार्वजनिक भवनों सहित प्रमुख नागरिक कार्यो के लिए 2022 – 23 में 290.58 करोड़ रुपये, 2023 – 24 में 287.99 करोड़ रुपये और 2024 – 25 में 62.92 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई, जबकि 2025 – 26 के लिए 125.06 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

ऊंचे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में सेवा वितरण की चुनौती को समझते हुए, सरकार ने दूरदराज के बस्तियों में बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं को सुदृढ़ किया है। स्वास्थ्य उप – केंद्रों का उन्नयन किया गया है, मोबाइल आउटरीच और रेफरल इकाइयां स्थापित की गई हैं, जबकि पेयजल और बिजली आपूर्ति को और अधिक विश्वसनीय बनाया गया है। बागवानी, पशुपालन और स्थानीय उपज के मूल्यवर्धन से जुड़ी आजीविका सहायता ने जनजातीय परिवारों की आय को स्थिर करने में मदद की है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, किन्नौर, पूह और स्पीति में 75 सीमांत बस्तियों के लिए विकास योजनाएं तैयार की गई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक अवसरों को मज़बूत करने के लिए विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। इन गाँवों में कनेक्टिविटी, आवास और सामुदायिक संपत्तियों पर काम शुरू हो चुका है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्र को भी प्राथमिकता पर रखा गया है। निचार, भरमौर, पांगी और लाहौल में चार एकलव्य म डल आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में 1,008 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जहां छठी कक्षा में हर साल 150 नए प्रवेश होते हैं। पांगी और लाहौल में नए स्कूल और छात्रावास परिसरों का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके लिए क्रमश: 2 करोड़ रुपये और 1.90 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने 20 – सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए 2022 – 23 में 7,502 परिवारों के मुकाबले 2023 – 24 में 8,598 परिवारों, 2024 – 25 में 6,573 परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले 12,663 परिवारों को कवर किया गया, जो लक्ष्य से लगभग दोगुना है। 2025 – 26 के लिए 6,314 परिवारों को लक्षित किया गया है।

वन अधिकार अधिनियम का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, जनजातीय जिलों में अधिकारियों और सामुदायिक प्रतिनिधियों को गहन प्रशिक्षण दिया गया। जून 2025 तक, 901 भूमि अधिकार जिनमें 755 व्यक्तिगत और 146 सामुदायिक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अप्रैल 2025 में लंबित दावों के एक समान और समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन कैलेंडर भी जारी किया गया है।

सरकार द्वारा स्थायी जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए 40.29 करोड़ रुपये की लागत से भूमि हस्तांतरण, वैधानिक मंज़ूरियां और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है, जो जनजातीय विकास के लिए अनुसंधान, क्षमता निर्माण और साक्ष्य – आधारित नीति निर्माण को गति प्रदान करेगा। निरंतर वित्त पोषण, मापनीय परिणामों और आवासीय विद्यालयों और एफआरए पट्टों के विस्तार से लेकर सीमावर्ती गांव के उन्नयन से लेकर विकास प्रस्तावित अनुसंधान संस्थान तक, संस्थागत निरंतरता के साथ, राज्य सरकार ने जनजातीय विकास को घोषणाओं से आगे बढ़ाकर जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष कार्यान्वयन की ओर अग्रसर किया है।

सरकार की पहल व विकास धरातल पर दिख रहा है और जनजनातीय समुदाय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है।

पारंपरिक चिकित्सा की बढ़ती प्रासंगिकता

जलवायु परिवर्तन और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के दौर में प्राचीन चिकित्सा पद्धति स्थायी स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदान कर सकती है

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय और राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, इसके 88 प्रतिशत सदस्य देशों – 194 देशों में से – 170 में पारंपरिक चिकित्सा का प्रचलन है। विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, यह चिकित्सा प्रणाली अपने सुलभ और किफायती सेवा के कारण अरबों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा का प्राथमिक रूप बनी हुई है। तथापि, इसका महत्व उपचार से आगे बढ़कर जैव विविधता संरक्षण, पोषण सुरक्षा और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने तक विस्तृत है।

व्यापारिक रुझान दिखाते हैं कि लोग इसे तेजी से अपना रहे हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा बाजार 2025 तक 10 प्रतिशत – 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 583 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। चीन का पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र 122.4 अरब डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का हर्बल औषधि उद्योग 3.97 अरब डॉलर और भारत का आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा एवं होम्योपैथी आयुष क्षेत्र 43.4 अरब डॉलर के मूल्य का है।

यह विस्तार स्वास्थ्य सेवा दर्शन में एक मूलभूत बदलाव को दर्शाता है – प्रतिक्रियात्मक उपचार मॉडल से सक्रिय, निवारक दृष्टिकोणों की ओर, जो केवल लक्षणों के बजाय मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

भारत का आयुर्वैदिक परिवर्तन

भारत के पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। 92,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों वाले आयुष उद्योग का एक दशक से भी कम समय में लगभग आठ गुना विस्तार हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र का राजस्व 2014 – 15 के 21,697 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्तमान में 1.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जबकि सेवा क्षेत्र ने 1.67 लाख करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

भारत अब 150 से ज्यादा देशों को 1.54 अरब डॉलर मूल्य के आयुष और हर्बल उत्पादों का निर्यात करता है और आयुर्वेद को कई देशों में एक चिकित्सा पद्धति के रूप में औपचारिक मान्यता मिल रही है। यह वैश्विक मंच पर आर्थिक अवसर और सॉफ्ट पावर, दोनों का प्रतिनिधित्व करता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय 2022 – 23 द्वारा आयुष पर किए गए पहले व्यापक सर्वेक्षण से लगभग सार्वभौमिक जागरूकता का पता चलता है – ग्रामीण क्षेत्रों में 95 प्रतिशत और शहरी केंद्रों में 96 प्रतिशत। पिछले वर्ष आधी से ज्यादा आबादी ने आयुष प्रणालियों का उपयोग करने की जानकारी दी थी और आयुर्वेद कायाकल्प और निवारक देखभाल के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरा है।

वैज्ञानिक मान्यता, वैश्विक विस्तार

भारत ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद सहित कई संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान में महत्वपूर्ण निवेश किया है।

ये संस्थान नैदानिक सत्यापन, औषधि मानकीकरण और एकीकृत देखभाल म डल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़ते हैं।

आयुष मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के माध्यम से भारत की वैश्विक आयुर्वेद पहुंच ने अभूतपूर्व स्तर हासिल किया है। भारत ने 25 द्विपक्षीय समझौतों और 52 संस्थागत साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए हैं, 39 देशों में 43 आयुष सूचना प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और विदेशी विश्वविद्यालयों में 15 शैक्षणिक विभागों की स्थापना की है।

भारत में डब्लूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत सरकार से समर्थन प्राप्त इस केंद्र का उद्देश्य आधुनिक विज्ञान, डिजिटल स्वास्थ्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का उपयोग करना है।

पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के एकीकरण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का हालिया प्रकाशन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे उन्नत प्रौद्योगिकियां नैदानिक सत्यापन को मजबूत कर सकती हैं, बड़े डेटा विश्लेषण को सक्षम बना सकती हैं और आयुर्वेद व संबंधित प्रणालियों में पूर्वानुमान देखभाल प्रणाली को बेहतर बना सकती हैं।

आयुर्वेद जन – जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए

आयुर्वेद का मूल दर्शन – शरीर और मन, मानव और प्रकृति, उपभोग और संरक्षण के बीच संतुलन – समकालीन चुनौतियों के लिए प्रासंगिक समाधान प्रस्तुत करता है। जहाँ एक ओर दुनिया जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, वहीं आयुर्वेद एक ऐसी रूपरेखा प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत और पृथ्वी के स्वास्थ्य, दोनों का समाधान करने में सक्षम है।

भारत वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। यह दृष्टिकोण निवारक, किफायती, समावेशी और स्थायी स्वास्थ्य देखभाल पर ज़ोर देता है। आयुर्वेद न केवल एक चिकित्सा प्रणाली, बल्कि एक कल्याण अभियान का प्रतिनिधित्व करता है, जो पारंपरिक ज्ञान को समकालीन आवश्यकताओं से जोड़ता है।

प्राचीन ज्ञान का आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय, पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्वास्थ्य संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सुविधा देता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की क्षमता की याद दिलाता है, जो लोग और अपनी पृथ्वी के संदर्भ में एक अधिक संतुलित और स्थायी भविष्य में योगदान दे सकती है।

मंडी जिला की 327 बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लगाया एक करोड़ 66 लाख 77 हजार का शगुन

प्रदेश सरकार द्वारा गरीब व जरूरतमंद वर्गो के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका लाभ उठाकर लाभार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है। मंडी जिला में भी पात्र बेटियों को इसका लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेकर मंडी जिला के सैकड़ों गरीब व जरूरतमंद परिवार अपनी लाडलियों के हाथ पीले कर पाए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की वर्तमान सरकार द्वारा अप्रैल, 2023 से जुलाई, 2025 तक इस योजना के अंतर्गत जिला मंडी में 327 जरूरतमंद परिवारों को 51 – 51 हजार रुपए रुपए की राशि शगुन के रूप में बेटियों की शादी के लिए प्रदान की गई है। जिस पर एक करोड़ 66 लाख 77 हजार रुपए की राशि प्रदेश सरकार द्वारा व्यय की गई है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जरूरतमंद बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपए किया गया है।

क्या कहते हैं लाभार्थी

पधर उपमंडल की गवाली के गांव पंडल की बनीता ने बताया कि उनकी बेटी वंदना की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51 हजार रुपए की राशि मिलने से उन्हें आर्थिक तौर पर काफी सहायता मिली है। राशि जारी करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

सरकाघाट उपमंडल के गांव मतलग फ़लाड की किरण कुमारी का कहना है कि इस योजना से उन्हें अपनी बेटी की शादी करने में काफी मदद मिली। उन्हें योजना के बारे आंगनवाड़ी सहायिका से पता चला। दस्तावेज़ पूरा करने के बाद तुरंत उन्हें 51 हजार की राशि मिल गई, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताया। वहीं किरण की बेटी कोमल ठाकुर का कहना है कि उनकी माता जी को इस वित्तीय मदद से शादी करने में काफी सहायता मिली जिसके लिए वह मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करती हैं।

सरकाघाट उपमंडल के गांव कलोट डाकघर रखोह की एक अन्य लाभार्थी मनीषा कुमारी की माता प्रोमिला देवी ने भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटी की शादी में 51 हजार की सहायता राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

लडभड़ोल के सिमस की मीरा देवी, करसोग के तेवन की दीक्षा कुमारी, थुनाग के गुनास की मथरू देवी तथा गोहर के कांडी टिल्ली की रचना देवी ने योजना के तहत बेटी की शादी में 51 हजार की सहायता राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

योजना का लाभ लेने के लिए क्या है पात्रता

जिन लड़कियों के पिता की मौत हो चुकी हो, या जिन लड़कियों के पिता पैसा कमाने में सक्षम न हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर बिस्तर पर हों, ऐसे पात्र लाभार्थियों को बेटी की शादी पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अभिभावकों की सालाना आय 50 हजार रुपए से कम होनी चाहिए तथा लडक़ी की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

शादी होने के छह माह तक भी कर सकते हैं आवेदन

जरूरतमंद परिवार अगर बेटी की शादी के समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन नहीं दे पाए, तो वह शादी के छह माह बाद तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अकसर देखने में आता है कि शादी में काफी इंतजाम करने के चलते कई लोग उक्त योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं तो ऐसे लोग शादी के छह माह बाद उक्त योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना के लिए ये दस्तावेज करवाने होंगे जमा

योजना का लाभ लेने के लिए लड़की का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, परिवार का आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जमा करवाने के साथ – साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी (एकीकृत बाल विकास परियोजना) अथवा अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा।

क्या कहते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी

जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय बदरेल ने बताया कि मुख्यमंत्रे कन्या योजना के तहत जिला मंडी की 327 बेटियों को वर्तमान सरकार द्वारा अप्रैल, 2023 से जुलाई, 2025 तक 51 – 51 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए उनके कार्यालय अथवा अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों के लिए यह योजना बहुत की कारगर है।

मुख्यमंत्री ने टूटीकंडी बाल आश्रम में बच्चों के साथ मनाई दिवाली

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने टूटीकंडी बाल आश्रम का दौरा किया और आश्रम में

रहने वाले बच्चों के साथ दीपोत्सव भी मनाया।

आश्रम के बच्चों और कर्मचारियों ने मिट्टी के दीये जलाकर और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को मिठाइयां और उपहार बांटे और उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली का असली मतलब खुशियां, करुणा और एकजुटता बांटना है। ये बच्चे हमारा भविष्य हैं और यह हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है, कि हम सुनिश्चित करें कि उनकी परवरिश प्यार, सम्मान और उचित अवसरों के साथ हों।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 'राज्य के बच्चों' के रूप में गोद लिया है। इन बच्चों की शिक्षा का सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रति माह 4000 रुपये पॉकेट मनी भी प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य के बाल आश्रमों में आवासीय सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा और अन्य सुविधाओं में भी वृद्धि की जाएगी।

सुक्खू ने कहा कि सरकार जल्द ही अनाथ और कमजोर बच्चों के समग्र विकास के लिए विशेष रूप से नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बाल आश्रम के बच्चों के लिए हर साल 14 नवंबर को खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार पर्याप्त बजट का प्रावधान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल आश्रमों के छात्रों को बेहतर अनुभव प्राप्त करने के लिए राज्य से बाहर शैक्षणिक दौरों पर भेजा जाएगा। उन्होंने बच्चों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और उसके बाद विभिन्न क्षमताओं में राष्ट्र की सेवा करके देश का नाम रोशन करने का आहवान किया।

इस अवसर पर महापौर सुरेन्दर चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, निदेशक महिला एवं बाल कल्याण पंकज ललित और उपायुक्त अनुपम कश्यप भी उपस्थित थे।

चमियाणा और टांडा के बाद आईजीएमसी शिमला में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी

शिमला/शैल। अटल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज (एआईएमएसएस),

चमियाणा और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत के बाद राज्य सरकार शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला में यह सुविधा उपलब्ध करवाने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आईजीएमसी शिमला में कमला नेहरू अस्पताल के मरीजों की रोबोटिक सर्जरी के लिए 40 बेड आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवा रही है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईजीएमसी में गाइनी की रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाए। बैठक में गाइनी की रोबोटिक सर्जरी से जुड़े अनेक अन्य निर्णय भी लिए गए। उन्होंने कहा कि केएनएच के स्त्री रोग विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जरी के अलावा आईजीएमसी में इलेक्टिव सर्जरी भी करेंगे। उन्होंने कहा कि केएनएच प्रशासन रोबोटिक व इलेक्टिव सर्जरी के लिए आईजीएमसी में डॉक्टरों की टीम तैनात करेगा ताकि दोनों जगह महिला रोगियों को सुगम इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में रोबोटिक व इलेक्टिव सर्जरी का तीन माह तक ट्रायल आधार पर प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद समीक्षा कर आगामी बदलाव किए जा सकते हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 25 करोड़ रुपये की लागत से आईजीएमसी में डायग्नोस्टिक लैब स्थापित की जा रही है। कॉलेज प्रशासन को इसके लिए राशि जारी कर दी गई है। इसमें टेस्ट शुरू होने के बाद केएनएच के स्त्री रोग विशेषज्ञों को भी महिला रोगियों के उपचार में काफी लाभ होगा।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा राकेश शर्मा तथा कमला नेहरू अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।

प्रदेश में म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर्स के लिए केंद्र से 47.37 करोड़ रुपये जारी:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर्स की स्थापना के लिए 47.37 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह स्वीकृति राज्य सरकार की पहल और निरंतर प्रयासों से संभव हुई है, जिससे सीमित जनशक्ति, वित्तीय संसाधनों की कमी और तकनीकी सहयोग की चुनौतियों का समाधान हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य शहरी शासन को सुदृढ़ बनाना, डिजिटल सेवा वितरण को बढ़ावा देना और कुशल नगरपालिका प्रशासन सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में 15 केंद्रों की स्थापना 74 शहरी स्थानीय निकायों में की जा रही है, जो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र नागरिकों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस, पालतू जानवरों के पंजीकरण, संपत्ति कर का भुगतान, कचरा बिल संग्रहण और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं तक आसान, एकरूप और पारदर्शी पहुंच प्रदान करेंगे। ये केंद्र पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर कार्य करेंगे।

उन्होंने कहा कि ये केंद्र शहरी निकायों के सदस्यों के लिए लेखा, वेतन प्रबंधन और विक्रेता भुगतान जैसी गतिविधियों के केंद्रीकृत केंद्र के रूप में भी काम करेंगे। साथ ही, छोटे कस्बों में टैक्स और बिल संग्रहण जैसी सेवाएं भी घर-घर प्रदान करेंगे।

मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार दो किस्तों में धनराशि जारी करेगी। स्वीकृति के समय 50 प्रतिशत राशि जारी की जाएगी और शेष राशि परिचालन शुरू होने पर दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 23.68 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जो इन केंद्रों की संस्थागत और परिचालन क्षमता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि समावेशी कार्यान्वयन और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों को वार्ड स्तर पर नगरपालिका सेवाओं के वितरण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया जाएगा, जिससे नागरिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और 'स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर' के दृष्टिकोण के अनुरूप सहभागी, कुशल और सतत शहरी शासन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पांगी में प्राकृतिक जौ की खरीद शुरू, 59 किसानों से 140 क्विंटल की खरीद

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने चंबा जिला के पांगी उपमंडल में प्राकृतिक खेती से तैयार जौ की खरीद शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान खरीफ सीजन में अब तक पांगी उपमंडल के 59 किसानों से 140 क्विंटल प्राकृतिक जौ 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई है।

ग्राम पंचायत हुडान के 11 किसानों से 20 क्विंटल, सुराल के 24 किसानों से 78 क्विंटल, किलाड़ के 7 किसानों से 9 क्विंटल, साच के 7 किसानों से 10 क्विंटल और सेचू पंचायत के 10 किसानों से 23 क्विंटल जौ की खरीद की गई है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल दिवस समारोह के अवसर पर चंबा जिला के पांगी को राज्य का पहला 'प्राकृतिक खेती उपमंडल' घोषित किया गया था।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है ताकि लोगों को रसायन-मुक्त अनाज और मसाले उपलब्ध हो सकें। सरकार प्राकृतिक फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इस पहल से किसान प्राकृतिक खेती अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नीतियां बना रही है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान खरीफ सीजन में 1473 किसानों से 2371.71 क्विंटल मक्की खरीदने का अनुमान है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में 28 संग्रह केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि विभाग किसानों से कच्ची हल्दी खरीद रहा है। इसके लिए 1629 किसानों से 2422.65 क्विंटल प्राकृतिक कच्ची हल्दी 12 संग्रह केन्द्रों के माध्यम से खरीदी जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार प्राकृतिक गेहूं और जौ पर 60 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की पर 40 रुपये प्रति किलोग्राम और कच्ची हल्दी पर 90 रुपये प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। यह कदम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उचित दाम सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव सामने आया है। किसान प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे आमदनी के साथ-साथ जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 'हरित दीपावली' के संदेश पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ और हरित

दिपावली मनाने के सन्देश के साथ राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान आयोजित किए। बोर्ड द्वारा बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, चम्बा, ऊना, सिरमौर, सोलन और हमीरपुर जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बोर्ड की परवाणु स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पट्टा मसूलखाना और परवाणु में 'हरित दीपावली' पहल के तहत 'स्वच्छ दीपावली, हरित दीपावली' विषय पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए। इस आयोजन में पटाखे फोड़ने के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। इसके पश्चात् विद्यार्थियों द्वारा थीम पर आधारित नारा लेखन और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

इसी प्रकार, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पांवटा साहिब ने भी सिरमौर जिला के पीएम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय बेचड़ का बाग में 'स्वच्छ दीपावली, हरित दीपावली' विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों और समुदाय को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल दीपावली मनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर बनाने, नारा लेखन और भाषण जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को ग्रीन दीपावली के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपनी कलाकृतियों और भाषणों के माध्यम से प्रभावशाली संदेश दिए।

प्रधान विज्ञानी डॉ. हितेंद्र कुमार शर्मा ने पटाखों के दुष्प्रभावों पर एक व्याख्यान दिया और सभी से स्वस्थ पर्यावरण के लिए दीपावली मनाने का एक पर्यावरण-अनुकूल तरीका चुनने का आग्रह किया।

विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उनके सराहनीय प्रयासों के लिए प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, घनियारा में भी दीपावली जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विद्यार्थियों ने रैली के माध्यम से स्वच्छ एवं हरित दीपावली का संदेश दिया।

क्षेत्रीय प्रयोगशाला दारी की विज्ञानी सतविंद्र कौर ने अपने सम्बोधन में पर्यावरण के अनुकूल दीपावली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

दीपावली के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को अनंत मंगलकामनाएँ देता हूँ। यह पर्व आपके जीवन में उत्साह, उल्लास और खुशियाँ लेकर आए। हिमाचल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ जलवायु के लिए विश्वविख्यात है। प्रदेश सरकार 'हरित हिमाचल' बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूँ कि इस दीपावली को 'प्रदूषण-मुक्त दीपावली' के रूप में मनाएँ और 'स्वदेशी उत्पादों' व 'स्थानीय कारीगरों' का समर्थन करें।

आइए, हम मिलकर हरित, आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल के निर्माण में अपना योगदान दें।

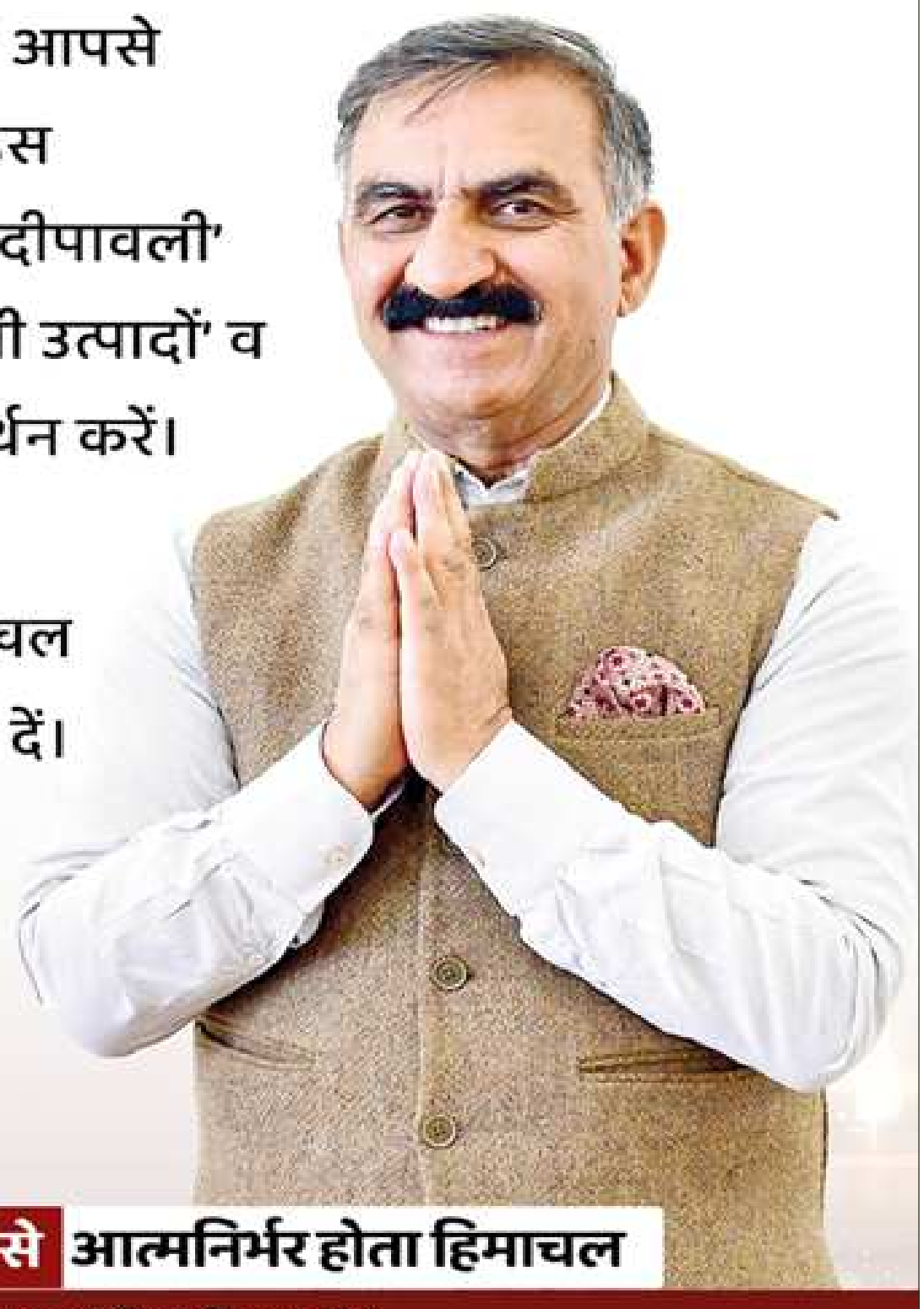

सुखविन्द्र सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर होता हिमाचल

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

प्रदेश सरकार आज हर मोर्चे पर नाकाम:जयराम

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश

सरकार आज हर मोर्चे पर नाकाम है। प्रदेश के पेंशनर्स सड़कों पर हैं। अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश का कर्मचारी वर्ग भी सड़कों पर है। एचआरटीसी कर्मी भी अपना हक मांग रहे हैं। पेंशनर्स को जीवन भर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की सेवा करने के बाद उम्र के इस पड़ाव पर अपने मेडिकल बिलों का भुगतान तक नहीं हो रहा है। ऐसे में तीन-तीन साल तक इलाज के बिलों के भुगतान की राह तकना किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी के लिए बहुत मुश्किल है। हिम केयर का पैसा रोककर यह सरकार प्रदेश वासियों से संविधान प्रदत्त जीवन का अधिकार भी छीन रही है।

आपदा की वजह से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी एक पैसे की भरपाई अभी तक नहीं हो पायी है। बारिश का मौसम बीत गया है और सर्दियां सिर पर आ गई हैं लेकिन आपदा से किया गया कोई भी वादा सरकार निभा नहीं पायी है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये कर्ज के आंकड़ों को छुपा रहे हैं। सुक्खू सरकार ने 34 महीने के कार्यकाल में ही लगभग 40 हजार करोड़ का कर्ज ले लिया है। यानी हर महीने 1100 करोड़ से अधिक का कर्ज यह सरकार ले रही है। दुख इस बात का है कि यह आंकड़ा हर तिमाही में बढ़ता जा रहा है। सुक्खू सरकार द्वारा प्रदेश के ऊपर नाना प्रकार के टैक्स थोपे जा रहे हैं। यह सरकार यदि अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी तो कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अपनी नाकामी छुपाने के लिए यह सरकार हर दिन पूर्व की भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर अनर्गल बयानबाजी करती है। जबकि हकीकत यह है कि मोदी सरकार द्वारा 5500 करोड रुपए से ज्यादा की नकद आर्थिक सहायता आपदा राहत के तौर पर दी जा चुकी है और उसमें से सरकार 300 करोड रुपए ही आपदा प्रभावितों पर खर्च कर पायी है।

जयराम ठाकुर ने बद्दी में हुए गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और दबंग पूरी तरीके से बेकाबू हैं। पुलिस अपराध नियंत्रण के अलावा सत्ता संरक्षण के अन्य कार्यों में व्यस्त है।

डीए में मुख्यमंत्री ने किया 1 प्रतिशत का हेर फेर:सिकंदर

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद डॉ. सिकन्दर कुमार ने कहा कि डीए की घोषणा

में भी मुख्यमंत्री ने एक प्रतिशत का हेर फेर कर दिया। मुख्यमंत्री को पता है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति गंभीर कर दी है और वित्त विभाग को वेंटिलेटर तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है।

मुख्यमंत्री ने 01.07.2023 से 3 प्रतिशत डीए वृद्धि (कुल डीए 45 प्रतिशत) की घोषणा की है, जबकि केंद्र सरकार ने 01.07.2023 से 4 प्रतिशत (कुल डीए 46 प्रतिशत) की वृद्धि की थी। राज्य सरकार के इस निर्णय से कर्मचारी 01.07.2023 से देय डीए से वंचित हो गये हैं।

इसमें सीधा-सीधा दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री ने एक प्रतिशत कर्मचारियों का हक छीन लिया है, उनकी मंशा ही नहीं है कि वह कर्मचारी के बारे में सोचे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तो यह भी कह दिया कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है इससे साफ होता है कि कर्मचारी रखने में भी मुख्यमंत्री परहेज कर रहे हैं। कहां गई मुख्यमंत्री की वह घोषणा की वह पहली कैबिनेट में एक लाख नौकरियां देंगे और 5 साल में 5 लाख।

मुख्यमंत्री केवल एक ही चीज में विश्वास रखते हैं रिंप्लायमेंट, जिससे न कर्मचारी रखे जाएंगे और युवा भी नौकरी के अधिकार से वंचित रहेंगे। इस निर्णय से तो जिन कर्मचारियों की पदोन्नति होनी है उस पर भी ग्रहण लग गया है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की तीन किश्तें (01.07.2023 से 4%, 01.01.2024 से 4%, 01.07.2024 से 3%, कुल 11%) देय हैं । यह भी सत्य है कि सरकार ने दिनांक 01.07.2022 व 01.01.2023 को देय महंगाई भत्ते के एरियर का अब तक भुगतान नहीं किया है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान करने में विलम्ब हो रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर बात पर कहते हैं कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है अगर आपसे प्रदेश नहीं चलता तो आप गद्दी छोड़ दीजिए भाजपा सत्ता चलाएगी और वित्त स्थिति भी ठीक करेगी।

प्रदेश के सभी जिलों के आपदा प्रभावितों को दिया जाये विशेष राहत पैकेज:रणधीर

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार इस

साल आयी आपदा के लिये गंभीर नहीं है। इस बार हम सब जानते हैं पूरे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ है, कोई भी जिला इससे अछूता नहीं रहा है। अगर इसकी गंभीरता को देखना है तो पूरे प्रदेश में जहां 1736 मकान सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुये हैं। वहीं 7000 से ज्यादा मकान आंशिक रूप से जो है वो क्षतिग्रस्त हुये हैं और 8000 के लगभग पशुशालाएं गिरी, 300 के लगभग लोगों की जाने गयी, जबकि 50 के लगभग लोग लापता है। इतने भारी नुकसान के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। 2023 में आयी आपदा में मुख्यमंत्री सुखविंदर ने एक विशेष राहत पैकेज पूरे प्रदेश के लिये दिया था। जिसके तहत जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान है उनके लिए 7 लाख का प्रावधान था। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 1 लाख देने की वहां घोषणा की गयी थी।

रणधीर ने कहा कि परन्तु इस साल सिर्फ मंडी जिला के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की गयी है। अन्य जिले इससे वंचित हो गये हैं। इसलिये भाजपा की मांग है कि इस बार आयी आपदा के लिये पूरे प्रदेश में सभी जिलों में विशेष राहत पैकेज दिया जाये और प्रभावित लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाये। हमारा आरोप है कि सरकार की तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी आपदा को गंभीरता से नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता चाहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, कोई भी नेता आपदा के दौरान प्रभावितों से मिलने नहीं आया, संवेदना प्रकट नहीं की, किसी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया। जबकि आज वो एक राजनीतिक पर्यटक के तौर पर हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों का नजारा लेने आ रहे हैं। जबकि भाजपा के नेताओं ने इस बार आयी आपदा को भी 2023 की तरह पूर्ण रूप से गंभीरता से लिया, हमारे सभी सांसदों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। विधायक अपने क्षेत्रों में लगे रहे और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रभावित लोगों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और प्रधानमंत्री ने तो 1500 करोड़ देने की घोषणा की। यही नहीं इस घोषणा के अलावा भी 136 करोड़ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एसडीएमएफ के तहत हिमाचल प्रदेश को आ चुके हैं। अगर हम देखेंगे एनडीआरएफ के तहत 591 करोड़ 56 लाख, एसडीआरएफ के तहत 397 करोड़ 60 लाख और एसडीएमएफ के तहत 49 करोड़ 70 लाख प्रदेश को आये हैं। यह 1038 करोड़ जो प्रदेश को आये हैं अभी तक इसको भी यह सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। सड़कें बाधित है, टूटी हुई है उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही। पीने के पानी की स्कीमें दुरुस्त नहीं हो पा रही। कई गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंचा पायी है सरकार। कांग्रेस सरकार इस आपदा को लापरवाही से ले रही है और गंभीरता इसमें बरत नहीं रही है। हम उस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस सरकार ने इस आपदा के दौरान प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज पूरे प्रदेश में जारी नहीं किया तो भाजपा आंदोलन करने पर मजबूर होगी।